LOK SABHA

Monday, February 27, 1978/Phalguna 8, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

छोटे सिंचाई प्रोग्राम सम्बंधी राज सहायता योजना

*81. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटे सिंचाई प्रोग्रामों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान राज सहायता योजना का विस्तार करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). A proposal to make subsidy available under a Centrally Sponsored Scheme to small and marginal farmers for private minor irrigation works outside the areas covered under Central Sector projects, such as Small Farmers Development Agencies, Drought Prone Area Programmes, Integrated Tribal Development Programmes and Command Area Development Programmes is under consideration.

श्री हरगोविन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में छोटे किसानों को जो ऋण दिए गए, उन में इन्जिन डीलर्स और बैंकों के कर्मचारियों में बहुत जबर्दस्त शोषण किया है, उन को धोखा दिया है और अब उन की जमीनें नीलाम की जा रही हैं। क्या सरकार उन को ऋणों की अदायगी में कोई सुविधा देने का विचार कर रही है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह सवाल सब्सिडी के बारे में था, जिस का मैंने जबाव दिया है। कुछ इन्जिन वालों या बैंक कर्मचारियों ने उन को लूटा है, जैसा माननीय सदस्य बतला रहे है, इस के बारे में अभी हमारे ध्यान में कोई बात नहीं आई है।

श्री हरगोविन्द वर्मा : यह ठीक है कि मंत्रालय की तरफ से सब्सिडी देने का काम हुआ है और आगे भी देने की आप की योजना है, लेकिन सब्सिडी की लालच में जब किसान रुपया लेने बैंक में जाता है तो बैंक कर्मचारी उस को धोखा देकर उस से कमीशन लेते हैं, गलत माल देते हैं, जिस की वजह से उन को दिए गए इन्जिन्ज काम नहीं करते हैं। आप आज के अखबार में देखें—वसूली का समय आ गया है, सैकड़ों किसानों की जमीनें नीलाम पर चढ़ाई जा रही है, जबकि वास्तव में उन का पैसा नहीं मिला था और यदि मिला भी था तो बहुत कम मिला था, जिस से काम नहीं चल सकता था। उन की छोटी-छोटी जमीनें बिक रही हैं, इस के लिए आप क्या इन्तजाम करेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : असल में यह काम स्टेट गवर्नमेंटस का है कि वे देखें कि पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस तरह से उन को कर्ज दिया जाता है, कोई स्माल और मर्जिनल फार्मर्स को लूट तो नहीं

रहा है या बैंक वाले तो उन को नहीं लूट रहे हैं। जैसा मेम्बर साहब बतला रहे हैं कि कुछ बैंक कर्मचारी ऐसे हैं जो रिश्वत लेते हैं, मैं समझता हूं कि आप यह बात स्टेट गवर्नमेंट की नालिज में लायें, ताकि उन के खिलाफ मुनासिब कार्यवाही की जा सके। मैं भी यही समझता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाना चाहिए।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितनी कितनी धनराशि सहायता के रूप में राज्य सरकारों को देने का निश्चय किया है ? क्या यह बात सही है कि राज्य सरकारों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार जो पैसा आपसे मांगा है, वह पैसा देने में आपको कठिनाई हो रही है ? क्या ऐसी राज्य सरकारें भी है जो अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की राशि से 70—80 प्रतिशत राशि सिंचाई योजनाओं पर खर्च करने वाली हैं ? ऐसी परिस्थिति में आप क्या उन्हें विशेष सहायता केन्द्रीय कोष से देंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह सवाल इससे नहीं उठता है। सवाल यह है whether it is a fact that Government have decided to extend the present subsidy scheme with a view to encourage minor irrigation programmes.

श्री हुकम चन्द कछवाय : केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता के रूप में कितना पैसा देने का निश्चय किया है और उन सरकारों ने कितना मांगा है ? यह जवाब देने में क्या दिक्कत आ रही है ?

MR. SPEAKER: He cannot answer without notice; he has not got the material.

श्री हुकम चन्द कछवाय : इससे यह सवाल निकलता है।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: May I suggest to the hon. Minister to accept a short notice question to be given by Mr. Kachwai.

MR. SPEAKER: You give notice.

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : आप मुझे इसके बारे में नोटिस दीजिए, मैं इस बात की आपको जानकारी दूंगा।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: There are many regions and states which are suffering from serious imbalances and they are having irrigated lands for below the national level. In that context, has any special priority been fixed or special allocations being contemplated to be made for such regions and states, if so, the details thereof, if not, the reasons therefor?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: The question is not of small or minor irrigation but regarding subsidised schemes. If the hon. Member wants specific information regarding irrigation, let him put the question that way and I shall supply the information.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि सरकार ने छोटे सिंचाई प्रोग्रामों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान राज्य सहायता योजना का विस्तार करने का निश्चय किया है, यह प्रश्न है ?

SHRI JJYOTIRMOY BOSU: We are now taking about giving subsidy for minor irrigation for different states. In that context I am asking the regions where there are irrigated-area-figures below the national average and whether in the matter of granting subsidy any special consideration is shown, if not the reason thereof?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Subsidy is granted only for the centrally sponsored schemes: small farmers development agency, drought prone area programmes, integrated tribal development programme and command area development programme. These are the four programmes under which subidies are being given. This has

been taken up in about 3000 blocks out of 5026 blocks; so that area has been covered and in those areas subsidies are being allowed. It is not allocation to States.

SHRI JOTIRMOY BOSU: I used the word 'regions' priority for backward areas.

श्री लाल जी भाई : तीन साल के दौरान केन्द्र ने किस-किस राज्य को कितनी-कितनी राशि छोटे किसानों के लिए दी है। कछवाय जी ने यही मालूम करने की कोशिश की है और मंत्री जी टालमटोल कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि तीन साल में प्रान्तवार कितनी-कितनी पूंजी केन्द्रीय सरकार ने छोटे किसानों के लिए दी है? मैं यह भी जाना चाहता हूं कि छोटे किसानों से जो ब्याज लिया जाता है उसको माफ करने पर भी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें विचार कर रहीं हैं? यदि नहीं तो इस का क्या कारण है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : पहला सवाल तो उन्होंने यह पूछा है कि कितनी राशि तीन साल में खर्च हुई है या दी गई है। मेरे पास जो थोड़े थोड़े आंकड़े हैं वे मैं बता देता हूं। 1974–75 में डी पी ए पी के नीचे 7 करोड़ 22 लाख रुपया, 1975–76 में 8 करोड़ 70 लाख रुपया और 1976–77 में 14 करोड़ 10 लाख रुपया खर्च हुआ और इस साल भी आशा है कि तकरीबन इतना ही खर्च होगा। इसी तरह से आई टी डी पी के नीचे 1976-77 में 9 करोड़ 65 लाख और 1977–78 में 12 करोड़ 44 लाख रुपया। इसी तरह से सी ए डी पी के नीचे 1975–76 में 1 करोड़ 12, 1976-77 में 2 करोड़ 53 लाख और 1977–78 में अंदाजा है कि 3 करोड़ 84 लाख रुपया खर्च होगा।

श्री लाल जी भाई : विना ब्याज ऋण क्या आप देंगे या ऋण माफी के बारे में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता है।

श्री लाल जी भाई : दर कम करने पर विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नो, नो।

श्री राम मूर्ति : मंत्री जी को मालूम होगा कि प्रैक्टिस यह है कि सब्सिडी के मामले में जो लोग एप्लीकेशन ब्लाक लेवल पर देते हैं तो हर ब्लाक में कुछ इंजन मखसूस कर रखे गए हैं और एप्लीकेंट्स को मजबूर किया जाता है कि उन में से ही किसी को वे छांट ले। उन में से कोई अच्छा होता है और कोई नहीं भी होता है। इस तरह से वह आदमी बंध जाता है और मजबूर हो कर उनको पैसा भी देना पड़ता है। क्या कोई ऐसी स्कीम आपके दिमाग में है या ऐसी इंस्ट्रक्शंज इशू करने पर विचार कर रहे हैं कि देश के अन्दर कुछ खास किस्म के जो अच्छे इंजन माने जाते हैं उनकी लिस्ट बना दी जाए और उन में से किसी को भी वे लोग छांट ले और उनको किसी भी प्रकार से मजबूर न किया जाए कि वे कोई खास किस्म का इंजन ही लें। वे स्वछंदतापूर्वक काम कर सकें क्या इस पर आप ध्यान देंगे।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : अब भी कुछ खास किस्म के इन्जनों की लिस्टें बनती हैं स्टेट वाइज। कुछ स्टेट में भी तैयार होते है, बिग हाउसिस किर्लोस्कर वगैरह बनाते हैं। ब्लाक्स में जो लिस्टें रहती हैं उन पर माननीय सदस्य एतराज कर रहे हैं। यह भी कहा गया है कि उन में से कुछ खराब होते हैं। जब बाजार में कोई चीज ली जाती है तो कोई न कोई खराब भी निकल आती है। लिस्टें इस खयाल से तैयार की गई हैं कि अच्छे इंजन किसानों को मिल सकें। हर किसान यह नहीं जानता है कि कौन सा मेक अच्छा हैं। माननीय

सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि सेंटर से कोई लिस्ट बना करके दे दी जाए। उस पर भी ऐसा ही एतराज हो जाएगा, उस में से भी हो सकता है कि कोई खराब निकल आए। ट्रैक्टरों में से दो तीन पंजाब में भी अच्छे नहीं चले और उस पर एजीटेशन हुआ सेंटर के विचाराधीन ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद : छोटे किसानों को सहायता देने की स्कीम के अन्तर्गत किसानों के बहुत से समूह ऐसे हैं जो उन नदियों की अगल बगल या नदी दोआब में रहते हैं जो बहुत छोटी जोत के कृषक हैं और वे इस सहायता से वंचित रह जाते हैं। क्या सरकार ऐसे छोटे किसानों का सर्वेक्षण कराएंगी ताकि उनको भी वित्तीय सहायता मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : यह एराइज़ नहीं होता है।

श्री फिरंगी प्रसाद : कुछ ब्लाक्स को सरकार ने लिया है। क्या सरकार नया सर्वेक्षण कराएगी ताकि जो उपेक्षित भूभाग हैं उनको लिस्ट में जोड़ा जा सके ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: While the subsidies involve the problem of administration, sometimes administrative mal-practices creep in. I would like to know whether the hon. Minister would look into this fact that recently the development of agricultural irrigation has slowed down and it is likely to adversely affect the development of agriculture and agricultural production. To my mind unless the Ministry makes proper assesment of the problem increasing the subsidy may not be a solution to the problem.

MR. SPEAKER: That is a suggestion.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I would like to know his reaction.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: The speed of development of minor irrigation has not slowed down. It has rather improved considerably. We are not depending only on giving subsidy. This is only given to the marginal farmers, small farmers and community works. In other places, minor irrigation work is being stepped up. In fact, we are doing about twice as much as what was being done previously.

President Sahitya Akademi

*83. SHRI SAUGATA ROY: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the Sahitya Akademi has been without a President for very long;

(b) whether this has seriously affected the work of the Akademi; and

(c) the action Government propose to take in this matter?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) After the demise of Dr. Suniti Kumar Chatterji on 29-5-1977, Dr. K. R. Srinivasa Iyengar, Vice-President was designated as Acting President by the Executive Board of the Sahitya Akademi till Prof. Umashankar Joshi was elected as President on 4-2-1978 in accordance with the provisions of the constitution of the Akademi.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

SHRI SAUGATA ROY: The Minister rightly mentioned that on 29-5-1977 Dr. Suniti Kumar Chattopadhyaya, the former President, expired and new President was appointed only on 4-2-78. I put in my question on 31-1-78 and I am thankful to the minister that after I had put my question at least he appointed the new President. The